कथा क्रम

जुलाई–सितम्बर, 2025
मूल्य – ₹ 60

कथासाहित्य कला एवं संस्कृति की त्रैमासिकी

ISSN-2231-2161

वर्ष : 27 अंक : 105

जुलाई-सितम्बर 2025

कथा क्रम

कथासाहित्य, कला एवं संस्कृति की त्रैमासिकी

कहानियां

15 दीपक शर्मा : दाहिने हाथ

19 राजेन्द्र लहरिया : आर्त्तदण्ड (एक लापता राजा की हैरानकुन दास्तान : उर्फ़ नये समय की दंतकथा)

30 उर्मिला शिरीष : पराजय के समीकरण

35 संजय सिंह : गोबर का पहाड़

40 फ़रज़ाना महदी : सफ़र

55 विनीता शुक्ला : वर्जित स्वर

61 मनोशी चटर्जी : बचपन का सावन-एक दास्तां

66 इन्द्रजीत कौर : माउथ ऑर्गन

72 धीरेंद्र कुमार पटेल : अहेर हुयी आंखें

78 यासुनारी कावाबारा : मस्सा
अनुवाद- सुशांत सुप्रिय

लघुकथाएं

14 शिरोमणि राम महतो : दूध के दांत

29 किसलय पंचोली : सातिये ही सातिये!

34 डॉ. ईशान त्रिपाठी : सेल्फ

कथा-नेपथ्य

05 मधुरेश : मेरी जिंदगी में शरच्चन्द्र

साक्षात्कार

11 पल्लवी मिश्रा : डॉ. सूर्यबाला दुखों के सार्वभौमिक बनाती है कलम...

लेख

45 कंवल भारती : भगत सिंह की दृष्टि में अछूत समस्या

51 मनोज शर्मा : 'मेरे राम का मुकुट भींग रहा है' : परम्परा और आधुनिकता का समन्वय

कविताएं

83 चंद्रेश्वर : कविता और यूटोपिया, यही समय होता, लिबास पर एक नजर जरूर जाती है, दुनिया बदल गयी कितनी

85 शंकरानंद : टूटते हुए पुल, किनारे पर

86 सुधीर कुमार सोनी : रेल मार्ग/सड़क मार्ग, सूरज, जूते....

संस्मरण

87 रूप सिंह चंदेल : ए.वी. मिल्युकोव की यादों में दास्तोएवस्की

कथा-शोध

91 ज्योति कुमारी : अलका-सरावगी के उपन्यासों में भूमण्डलीकरण का प्रभाव

समीक्षाएं

97 डॉ. मधु संधु : अर्कदीप्त-अपनत्व और अस्मिता की खोज (उपन्यास : उषा प्रियंवदा)

100 नमिता सिंह : नक़्शे में समाया अनुभव और स्मृतियां (संस्मरण : प्रो. सूरज पालीवाल)

103 मनीष वैद्य : साफ़गोई से अपने समय और समाज की बातें करती प्रतिनिधि कहानियां (कहानी संग्रह : उर्मिला शिरीष)

106 नीरज नीर : मानवीय संवेदनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति : ज़ोया देसाई कॉटेज (कहानी संग्रह : पंकज सुबीर)

2 सम्पादकीय : सियासी पेंच में फंसी 'राजभाषा'....।'

आवरण : **बंसीलाल परमार**

रेखाचित्र : **राजेन्द्र परदेशी**

संपादक

शैलेन्द्र सागर

संपादन परामर्श

रजनी गुप्त

सहयोग

मीनू अवस्थी

प्रबन्ध सहायक

राम मूरत यादव

संपादन संचालन : अवैतनिक

संपादकीय सम्पर्क :

डी-107, महानगर विस्तार, लखनऊ-226006

दूरभाष : 09415243310

e-mail : kathakrama@gmail.com

e-mail : kathakrama@rediffmail.com

इस अंक का मूल्य : 60 ₹

सदस्यता शुल्क : व्यक्तिगत त्रैवार्षिक-900 ₹, आजीवन 4000 ₹

संस्थाएं : वार्षिक-400 ₹, त्रैवार्षिक-1100 ₹, आजीवन 5000 ₹

(kathakram SBI, Mahanagar Branch, Lucknow A/c 10059002392 IFSC-SBIN0008189)

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

मुद्रक : प्रकाश पैकेजर्स, प्लाट नं. 755/99 A, गोयला इनडस्ट्रियल एरिया, यू.पी.एस.आई.डी.सी.-देवा रोड, चिनहट, लखनऊ-226019

सियासी पेंच में फंसी 'राजभाषा...!'

पिछले दिनों अनेक मुद्दों ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है जो सब बेहद अहम हैं। एक तरफ हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिष्ठित और प्रतिस्थापित करने का दावा है, यूएनओ में मान्यता दिलाने की मुहिम है और लगातार बढ़ती जनसंख्या और लोकप्रियता को लेकर हिंदी भाषियों में गर्वानुभूति है, वहीं दूसरी ओर देश के भीतर ही उसकी मान्यता को लेकर विरोध एवं विद्रोह है जो कहीं हिंसा का समर्थन करता है। यह तब है जब हिंदी भाषा को लेकर कुछ नया नहीं हुआ है। अब तो नई शिक्षा नीति लागू किए भी पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। (नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जुलाई 2020 में लागू की गई थी जिसने 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लिया है।) तीन भाषा पॉलिसी भी खासी पुरानी है जिसे कोठारी आयोग की संस्तुति के फलस्वरूप वर्ष 1968 में प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करना था। इसी के चलते मेरे बीए अध्ययन के दौरान 1968 में हिंदी भाषा के विरोध में दक्षिण भारतीय राज्यों में उग्र प्रदर्शन हुए थे जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तर भारत में उसके समर्थन में व्यापक आंदोलन चला था। आंदोलनकारी छात्रों ने अध्यापन कार्य में व्यवधान डाला था और अन्य छात्रों को उसमें शामिल होने का आव्हान किया गया था। दक्षिण भारत में सबसे अधिक विरोध हिंदी फिल्मों को झेलना पड़ा था क्योंकि वे हिंदी का व्यापक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व एवं प्रचार करती थीं। उनके पोस्टरों को फाड़कर सिनेमाहाल, जहां उन्हें प्रदर्शित किया जा रहा था, को भी क्षतिग्रस्त किया गया। विदित है कि हिंदी फिल्में देश के सभी क्षेत्रों में बेहद लोकप्रिय रही हैं। तब आंचलिक भाषाओं की फिल्में की गुणवत्ता वो नहीं थी जो आज है। इसलिए अनेक दक्षिण भारतीय सिने निदेशक हिंदी में फिल्म बनाना पसंद करते थे जो पूरे देश में जबरदस्त कारोबार करती थीं।

धीरे धीरे यह विरोध क्षीण हो गया हालांकि आज भी दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी फिल्में तरह तरह के अवरोध सहती हैं। बैंगलोर जैसे आधुनिक मैट्रो नगर में भी यदाकदा ऐसा विरोध नजर आता है। अभी हाल में पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री ने आदेश दिया है कि हर थिएटर में प्रतिदिन एक शो में बंगला फिल्म चलाना अनिवार्य है।

वर्तमान में हिंदी विरोध की शुरुआत तमिलनाडू से हुई है जहां मुख्य मंत्री ने त्रिभाषा नीति के तहत हिंदी अध्यापन की अनिवार्यता के चलते राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू न करने की घोषणा कर दी और यह भी आरोप लगाया कि इस मुखालफत की वजह से केंद्र सरकार तमिलनाडू को निर्धारित अनुदान उपलब्ध नहीं करा रहा है। दक्षिण भारत के अन्य राज्यों ने भी कुछ दबे स्वर में तमिलनाडू को समर्थन दिया। तभी महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी हिंदी अध्यापन को अनिवार्य करने विषयक आदेश के विरोध में अपनी जमीन तलाश रहे राज ठाकरे ने मुम्बई में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिंदीभाषी लोगों के विरुद्ध हिंसक कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। यह कोई नया नहीं था। कुछ साल पहले भी एमएनएस के कार्यकर्ता उत्तर भारतीयों को अपनी हिंसा का शिकार बना चुके हैं। एक बार फिर आटो, टैक्सी चालकों, दुकानदारों वगैरह को खुलेआम मारा पीटा जा रहा है। जाहिरा तौर पर सरकार द्वारा 'कानून का राज' और 'सख्त कार्रवाई' का दावा किया जाता है किंतु होता कुछ नहीं है। एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी बिना